



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 108 राँची, शुक्रवार,

8 फरवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

05 फरवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-29/2016-448 (HRMS)—मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-165/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 05 मार्च, 2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1- मनरेगा के तहत योजना संख्या-52/2014-15 होलिका दहन से पक्की सड़क तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण कोड (346003015/RC/9931632911) में अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आपके द्वारा द्वितीय हस्ताक्षरी के रूप में 2,37,168.00/- रुपये की अवैध निकासी कर ली गयी है, जिससे प्रथम दृष्ट्या वित्तीय अनियमितता के संकेत मिलते हैं, जो मनरेगा अधिनियम एवं निर्देशों के अनुकूल नहीं है। मनरेगा के तहत यह आवश्यक है कि पंचायत सेवक, मुखिया एवं रोजगार सेवक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात ही राशि की निकासी की जाती है, परन्तु आपके द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से संबंधित प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र के बिना ही राशि की निकासी अवैध रूप से कर ली गई है, जिससे गबन का संदेह उत्पन्न होता है।

आरोप सं०-2- इस मामले में इस कार्यालय के पत्रांक 467 दिनांक 02 सितम्बर, 2015 द्वारा श्री अभिषेक कुमार प्रखण्ड नाजीर -सह- प्रथम हस्ताक्षरी मनरेगा पर वित्तीय अनियमितता के आरोप में तथा इस

कार्यालय के पत्रांक 465 दिनांक 02 सितम्बर, 2015 द्वारा श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर, मनरेगा बारियातु के विरुद्ध इनके द्वारा मनरेगा योजना में बरती गयी अनियमितता, मस्टर रौल में गड़बड़ी तथा निधियों के गबन के आरोप में दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के अनुरूप स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए थाना कांड संख्या के साथ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है। उक्त से आपकी स्वेच्छाचारिता, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं संलिप्त आरोपी को संरक्षण देने तथा नियमसंगत कार्रवाई के प्रति उदासीनता एवं समुचित अनुश्रवण का अभाव परिलक्षित होती है। इस संदर्भ में आपको इस कार्यालय के पत्रांक 527 दिनांक 16 सितम्बर, 2015, पत्रांक 2015 दिनांक 10 अक्टूबर, 2015, पत्रांक 594 दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक 144 दिनांक 01 मार्च, 2016 द्वारा कार्रवाई करने के लिए बार-बार स्मारित किया गया, जिसके पश्चात भी आपके द्वारा पूर्णरूपेण कार्रवाई नहीं की गई।

आरोप सं०-3- मिथिलेश के केशर से जबरा सीवान तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण:- उक्त योजना मनरेगा के तहत योजना संख्या-61/2015-16 है जिसकी कुल प्रशासनिक स्वीकृति राशि 5,64,500.00 रु० है। अभिलेख के अनुसार कनीय अभियंता के द्वारा 3,58,446.00 रु० की मापीपुस्त बनाई गई है। योजना में 1,74,960.00 रु० का भुगतान मजदूरी मद में किया गया है, परन्तु MIS के अनुसार 1,24,400.00 रु० ही मजदूरी मद में भुगतान किया गया है। प्रथम दृष्ट्या स्थलीय जाँच में पथ के आसपास कहीं भी मिट्टी कटाई का साक्ष्य दिखाई नहीं दिया। यह योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता का द्योतक है तथा इस योजना में अनियमितता के संदर्भ में आपके द्वारा कभी कोई सूचना विभाग या उच्च पदाधिकारियों को नहीं दी गई, जिससे आपकी मंशा पर संदेह उत्पन्न होता है तथा अनुश्रवण में लापरवाही परिलक्षित होती है।

आरोप सं०-4- ग्राम गाड़ी में तीनमुहान से लेकर देवीस्थान तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना संख्या-49/2014-15 पंचायत बारियातु के ग्राम-गाड़ी में संचालित है, अभिलेख के अनुसार योजना की प्राक्कलित राशि 8,69,600.00 रु० है जबकि MIS के अनुसार योजना का प्राक्कलन 9,10,000.00 रु० है। योजना का स्थलीय जाँच के क्रम में स्थानीय जाँच के क्रम में स्थानीय व्यक्ति प्रेमचन्द गंझू, पिता-रामविलास गंझू, आनंदी गंझू, पिता-गोविंद गंझू, दीपक कुमार, पिता-जगरनाथ साव सभी ग्राम-गाड़ी के द्वारा बताया गया कि कुछ दूरी में ही मिट्टी भराई का कार्य हुआ है। जाँच में यह पाया गया कि लगभग 100 मीटर में कुछ मिट्टी पथ पर बिछाया गया है, जबकि मापीपुस्त के अनुसार 2,52,302.00 रु० के कार्य का आकलन किया गया है। अभिलेख के अनुसार योजना में 2,85,768.00 रु० मजदूरी मद में भुगतान किया गया है, जबकि MIS में 2,56,900.00 रु० भुगतान मजदूरी मद में परिलक्षित हो रहा है। इस योजना के लिए भी स्थानीय पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के द्वारा किसी भी प्रकार के अभिलेख संधारण एवं भुगतान में अनभिज्ञता प्रकट किया गया है। स्थलीय जाँच में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भुगतान के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है, जिससे इस योजना में अनियमितता प्रदर्शित होती है। साथ ही इस योजना में अनियमितता के संदर्भ में आपके द्वारा कभी कोई सूचना विभाग या उच्च पदाधिकारियों को नहीं दी गई, जिससे आपकी मंशा पर संदेह उत्पन्न होती है तथा योजना कार्य के अनुश्रवण में लापरवाही परिलक्षित होता है।

आरोप सं०-5- प्रखण्ड के नाजीर से डोंगल लेकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा राशि की अनियमित निकासी:- इस संबंध में पूछताछ करने पर प्रखण्ड के नाजीर श्री अभिषेक कुमार जो कि प्रथम हस्ताक्षरी के रूप में डोंगल का संचालन करते थे, लिखित रूप में बताया गया कि दिनांक 21 जुलाई, 2014 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मो० अफताब आलम के द्वारा दबाव देकर डोंगल ले लिया गया उक्त तिथि के बाद नाजीर के द्वारा मनरेगा योजना के तहत डोंगल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपका यह कृत्य उपरोक्त मनरेगा योजनाओं में अवैध निकासी में संलिप्तता को प्रदर्शित करता है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3431, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 द्वारा मो० आलम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में मो० आलम के पत्रांक-628, दिनांक 05 अगस्त, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० आलम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7859, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-911, दिनांक 02 नवम्बर, 2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया।

मो० आलम के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9984, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-159, दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1996, दिनांक 19 मार्च, 2018 एवं पत्रांक-5597, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा मो० आलम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। इसके अनुपालन में मो० आलम द्वारा पत्र, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है।

मो० आलम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, मो० अफताब आलम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इन पर झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | MD. AFTAB ALAM JHK/JAS/162 | मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972